



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

सिविल अपील संख्या 534/2003

1. बतुराम उर्फ बतुल पिता श्री धुखू गोंड, सा. ग्राम-सकरपोगा, तहसील और जिला
- रायगढ़

----- अपीलार्थी

-:: बनाम ::-

1. श्रीमती सुकेत पति श्री उत्तरानिक गोंड, सा. हल्दीझरिया, वर्तमान पता ग्राम-
डुमरावली, पोस्ट बनौरा, तहसील और जिला-रायगढ़
2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर रायगढ़ (छ.ग.)

----- प्रतिवादी

अपीलार्थी	:	सुश्री शर्मिला सिंघई, अधिवक्ता
प्रतिवादी क्रमांक-01	:	श्री रामकुमार तिवारी, अधिवक्ता
राज्य	:	श्री विकास श्रीवास्तव, पैनल अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति मनींद्र मोहन श्रीवास्तव

आदेश बोर्ड पर

04/03/2020

1. यह अपील 29/07/2003 को द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा सिविल अपील संख्या 44 ए/2002 में पारित आलोच्य निर्णय और डिक्री के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा निचली अपीलीय अदालत ने वादी के मुकदमे को स्वीकार करते हुए वर्तमान अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा दायर की गई अपील को खारिज कर दिया है।



2. प्रतिवादी/वादी - सुकेत ने स्वामित्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा हेतु मुकदमा दायर किया, जिसमें यह तर्क दिया गया कि विवादित संपत्ति मूल रूप से गड़ा राय की थी और उनकी मृत्यु के बाद, यह अंजोर गोंड की पत्नी हीरामती के नाम दर्ज की गई। हीरामती वादी की मौसी थीं। अंजोर, हीरामती के पति, की 1980 में मृत्यु हो गई। हीरामती की 1999 में मृत्यु हो गई और अनुसूचित जनजाति के पारंपरिक उत्तराधिकार कानून के अनुसार, हीरामती की मृत्यु के बाद, क्योंकि उनके कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी, संपत्ति वादी - सुकेत को हस्तांतरित हो गई। प्रतिवादियों ने 19/03/1999 की वसीयत के आधार पर विवाद शुरू कर दिया, जिसके कारण वादी को मुकदमा दायर करने का कारण मिला। वादी ने यह घोषणा करने की प्रार्थना की कि 09/03/1999 की वसीयत को अमान्य, अप्रभावी घोषित किया जाए और प्रतिवादी को वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका जाए।

3. दूसरी ओर, प्रतिवादी - बतुराम ने यह मामला प्रस्तुत किया कि विवादित संपत्ति हीरामती की थी। हीरामती प्रतिवादी - बतुराम की सहायता से भूमि की खेती कर रही थीं और बतुराम हीरामती की देखभाल भी कर रहा था, और हीरामती ने पुरस्कार स्वरूप 09/03/1999 को उसके पक्ष में वसीयत बनाई।

4. चूंकि वादी और प्रतिवादी के मामले, संबंधित दलीलों में मुख्य रूप से वसीयत के मुद्दे और यह कि क्या कोई पारंपरिक कानून था जिसके तहत संपत्ति वादी को हस्तांतरित होगी, से संबंधित थे, निचली अदालत ने इन प्रश्नों को अन्य मुद्दों के साथ उचित मुद्दों का निर्धारण करके निर्णय लिया। हालांकि, निचली अदालत ने यह माना कि वसीयत संदिग्ध हैं, और यह पाया कि वादी ने पारंपरिक उत्तराधिकार कानून को साबित करने में विफल रही, जैसा कि उसने वादपत्र में दावा किया था, मुकदमे को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया कि वसीयत बाध्यकारी नहीं है। अन्य अनुरोधित राहतें प्रदान नहीं की गईं।

इस निर्णय और डिक्री से आहत होकर, वादी - सुकेत बाई और प्रतिवादी - बतुराम, दोनों ने अपनी-अपनी अपीलें दायर कीं। निचली अपीलीय अदालत ने भी



वसीयत के संदिग्ध होने के संबंध में निचली अदालत के निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की, लेकिन पारंपरिक कानून और मृतक की संपत्ति पर वादी के अधिकार के संबंध में निष्कर्ष को पलट दिया। यह माना गया कि वादी को मृतक – हीरामती की संपत्ति पर पारंपरिक उत्तराधिकार कानून के तहत अधिकार प्राप्त था। इस प्रकार, सुकेत की अपील स्वीकार कर ली गई और मुकदमे में मांगी गई सभी राहतें पूर्णतः प्रदान की गईं, जबकि बतुराम द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया, जिससे यह द्वितीय अपील उत्पन्न हुई।

5. यह अपील निम्नलिखित महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर स्वीकार की गई थी:-

"क्या निचली अदालतें यह मानने में उचित थीं कि प्रतिवादी ने 09/03/1999 (Ex.D.4) की हीरामती द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित वसीयत के उचित निष्पादन, साक्ष्यांकन और वैधता को कानून के अनुसार साबित करने में विफल रहा? "

6. अपीलार्थी के वकील ने तर्क दिया कि दोनों निचली अदालतों ने वसीयत को संदिग्ध मानने में गंभीर त्रुटि और स्पष्ट अवैधता की है, भले ही वसीयत का निष्पादन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (संक्षिप्त में 1925 का अधिनियम) की धारा 63 (सी) और साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षिप्त में 1872 का अधिनियम') की धारा 68 के कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार साबित किया गया था। अपीलार्थी के वकील ने दावा किया कि वसीयत को न केवल सुदामा (DW2) और सुरेश कुमार (DW3) के विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा साबित किया गया था, बल्कि नोटरी – जानकी प्रसाद (DW4) के साक्ष्य से भी साबित किया गया था। यद्यपि इन गवाहों के साक्ष्य को किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकी, निचली अदालतों ने वसीयत पर संदेह करने के लिए कुछ असंबंधित परिस्थितियों का सहारा लिया। यह तर्क दिया गया कि निचली अदालतों ने वसीयत पर संदेह इस आधार पर किया कि नोटरी टेस्टेटर से परिचित नहीं था; हीरामती की मृत्यु के तुरंत बाद वसीयत का खुलासा नहीं किया गया; वसीयत के निष्पादन में बतुराम ने सक्रिय भूमिका निभाई; हीरामती शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थीं; और प्रतिवादी ने यह स्पष्ट करने में



विफल रहा कि मंगलू के पक्ष में तैयार की गई वसीयत को बाद में रद्द क्यों किया गया और फिर बतुराम के पक्ष में नई वसीयत क्यों बनाई गई।

7. प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि दोनों निचली अदालतों ने समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्ष दर्ज किए कि वसीयत संदिग्ध है। वसीयत को संदिग्ध मानने के लिए, निचली अदालतों ने मृतक - हीरामती की स्वास्थ्य स्थिति, बतुराम द्वारा वसीयत के निष्पादन में सक्रिय भूमिका निभाने, हीरामती की मृत्यु के तुरंत बाद बतुराम का नाम प्रकट न करने, और पहले हीरामती द्वारा मंगलू के पक्ष में वसीयत बनाई गई थी लेकिन बाद में उसे रद्द कर बतुराम के पक्ष में नई वसीयत बनाई गई, जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखा है। यहां तक कि अगर वसीयत के गवाहों ने वसीयत के निष्पादन और उनके हस्ताक्षरों को साबित किया है, तो भी अन्य परिस्थितियों के आधार पर तथ्य निर्धारण करने वाली अदालतों के लिए वसीयत को संदिग्ध मानना उनके अधिकार क्षेत्र में है। उनके अनुसार, एक बार निचली अदालतों ने समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्ष दर्ज कर दिए हैं, तो अपीलार्थी के लिए कानूनी प्रश्न के बहाने साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने का कोई आधार नहीं है। उनका तर्क है कि इस मामले में कोई कानूनी प्रश्न विचारणीय नहीं है।

8. मैंने पक्षकारों के वकीलों की बातें सुनी हैं और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

9. इस मामले में, दोनों निचली अदालतों ने समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए हैं कि वसीयत संदिग्ध है। ऐसा मानते हुए, निचली अदालतों ने यह विशिष्ट निष्कर्ष नहीं दर्ज किया कि दोनों गवाहों के साक्ष्य को अविश्वसनीय क्यों माना जाए। निष्पादन के गवाहों के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर कोई गंभीर चुनौती न होने के बावजूद, निचली अदालतों ने वसीयत को संदिग्ध मानने के लिए कुछ आस-पास की परिस्थितियों का सहारा लिया।

10. यद्यपि, सामान्यतः द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन यह एक अटल नियम नहीं है। उचित मामलों



में, जहां अदालत को लगता है कि समवर्ती निष्कर्ष अवैध दृष्टिकोण, विपरीत या त्रुटिपूर्ण प्रकृति पर आधारित हैं या जहां पारित आदेश मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के गलत व्याख्या पर आधारित है, तो समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्षों में भी हस्तक्षेप किया जा सकता है।

11. इस मामले में, अपीलार्थी / प्रतिवादी ने वसीयत के निष्पादन को साबित करने के लिए वसीयत के दोनों साक्ष्य गवाहों – सुदामा (DW2) और सुरेश कुमार (DW3) – को पेश किया है। न केवल यह, बल्कि कानून की आवश्यकता न होने के बावजूद, नोटरी – जानकी प्रसाद (DW4) ने भी वसीयत के निष्पादन को साबित किया है, क्योंकि उनके अनुसार, यह उनकी उपस्थिति में निष्पादित की गई थी।

12. वसीयत के साक्ष्य गवाहों के साक्ष्य पर विचार करने से पहले, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 (सी) और साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 के तहत वसीयत के प्रमाण के कानूनी आवश्यकताओं के संबंध में स्थापित कानूनी स्थिति का उल्लेख करना उचित है। **मंटोरा बाई (मृत) बनाम गणेशिया बाई और अन्य** (सिविल अपील संख्या 130/2003) के मामले में, इस न्यायालय ने कई न्यायिक प्राधिकरणों के संदर्भ में कानूनी स्थिति की जांच की।

"10. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 (सी) में निहित प्रावधान वसीयत के निष्पादन के तरीके के बारे में विशिष्ट प्रावधान शामिल करते हैं। प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार है:—

"धारा 63 (सी) – वसीयत को दो या अधिक गवाहों द्वारा साक्ष्यांकित किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक ने टेस्टेटर को वसीयत पर हस्ताक्षर करते या निशान लगाते देखा है या किसी अन्य व्यक्ति को टेस्टेटर की उपस्थिति और निर्देश पर वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा है, या टेस्टेटर से उसके हस्ताक्षर या निशान, या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत स्वीकृति



प्राप्त की है; और प्रत्येक गवाह टेस्टेटर की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक से अधिक गवाह एक ही समय में उपस्थित हों, और साक्ष्यांकन के लिए किसी विशेष प्रारूप की आवश्यकता नहीं है।"

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि वसीयत के प्रमाण के मामले में विशेष कानून की आवश्यकता यह है कि वसीयत को साक्ष्य गवाह द्वारा साबित किया जाना चाहिए (i) जिसने टेस्टेटर को वसीयत दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करते या निशान लगाते देखा है, या (ii) जिसने किसी अन्य व्यक्ति को टेस्टेटर की उपस्थिति और निर्देश पर वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा है (iii) या जिसने टेस्टेटर से उसके हस्ताक्षर या निशान, या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत स्वीकृति प्राप्त की है।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 में सामान्य रूप से लागू होने वाला कानून, जिसमें उन दस्तावेज़ों के प्रमाण की आवश्यकता होती है जिन्हें कानून द्वारा साक्ष्यांकित करना आवश्यक है, इस प्रकार है: -

"धारा 68 : कानून द्वारा साक्ष्यांकित आवश्यक दस्तावेज़ के निष्पादन का प्रमाण- यदि किसी दस्तावेज़ को कानून द्वारा साक्ष्यांकित करना आवश्यक है, तो उसे तब तक साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके निष्पादन को साबित करने के लिए कम से कम एक साक्ष्य गवाह को नहीं बुलाया गया हो, बशर्ते कि ऐसा साक्ष्य गवाह



जीवित हो, अदालत की प्रक्रिया के अधीन हो और साक्ष्य देने में सक्षम हो:

[बशर्ते कि यह आवश्यक नहीं होगा कि किसी दस्तावेज़, जो वसीयत नहीं है, के निष्पादन को साबित करने के लिए साक्ष्य गवाह को बुलाया जाए, जिसे भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 1908 का 16) के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत किया गया है, जब तक कि उस व्यक्ति द्वारा निष्पादन विशेष रूप से इनकार न किया गया हो जिसके द्वारा यह दावा किया जाता है कि उसने निष्पादित किया है।] "

उक्त प्रावधान के अनुसार, जहां किसी पक्ष को कानून द्वारा साक्ष्यांकित करने की आवश्यकता वाले दस्तावेज़ के निष्पादन को साबित करना होता है, वह दस्तावेज़ तब तक साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता जब तक कि कम से कम एक साक्ष्य गवाह को नहीं बुलाया गया हो, बशर्ते कि ऐसा साक्ष्य गवाह जीवित हो और अदालत की प्रक्रिया के अधीन हो और साक्ष्य देने में सक्षम हो।

बंदिश वसीयत के मामले में लागू नहीं होती।

11. वसीयत के प्रमाण की कानूनी आवश्यकता को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और इस न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों में माना गया है। **जानकी नारायण भोईर बनाम नारायण नामदेव कदम, 2003(1) CGLJ 190** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय में उनके लॉर्डशिप ने वसीयत के प्रमाण की कानूनी आवश्यकताओं की जांच की:—

"7. हम उचित समझते हैं कि प्रासंगिक प्रावधानों, अर्थात् भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की



धारा 63 और साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 और 71 को देखें, जो इस प्रकार पढ़ते हैं:—

धारा 63 उत्तराधिकार अधिनियम की: " 63. अनाधिकृत वसीयतों का निष्पादन. प्रत्येक टेस्टेटर, जो एक सैनिक नहीं है जो किसी अभियान में नियुक्त है या वास्तविक युद्ध में संलग्न है, या एक वायुसेना का सदस्य ऐसे नियुक्त या संलग्न है, या समुद्र में एक नाविक, निम्नलिखित नियमों के अनुसार अपनी वसीयत निष्पादित करेगा:—

(क)

(ख)

(ग) वसीयत को दो या अधिक गवाहों द्वारा साक्ष्यांकित किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक ने टेस्टेटर को वसीयत पर हस्ताक्षर करते या निशान लगाते देखा है या किसी अन्य व्यक्ति को टेस्टेटर की उपस्थिति और निर्देश पर वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा है, या टेस्टेटर से उसके हस्ताक्षर या निशान, या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत स्वीकृति प्राप्त की है; और प्रत्येक गवाह टेस्टेटर की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक से अधिक गवाह एक ही समय में उपस्थित हों, और साक्ष्यांकन के लिए किसी विशेष प्रारूप की आवश्यकता नहीं है । "

धारा 68 साक्ष्य अधिनियम की: "68. कानून द्वारा साक्ष्यांकित आवश्यक दस्तावेज के निष्पादन का



प्रमाण - यदि किसी दस्तावेज़ को कानून द्वारा साक्ष्यांकित करना आवश्यक है, तो उसे तब तक साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके निष्पादन को साबित करने के लिए कम से कम एक साक्ष्य गवाह को नहीं बुलाया गया हो, बशर्ते कि ऐसा साक्ष्य गवाह जीवित हो, अदालत की प्रक्रिया के अधीन हो और साक्ष्य देने में सक्षम हो:

बशर्ते कि ..."

धारा 71 साक्ष्य अधिनियम की: "71. प्रमाण जब साक्ष्य गवाह निष्पादन को इनकार करता है. यदि साक्ष्य गवाह दस्तावेज़ के निष्पादन को इनकार करता है या याद नहीं करता है, तो इसके निष्पादन को अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है।"

8. यह कहने के लिए कि वसीयत का उचित निष्पादन हुआ है, उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के खंड (क), (ख), और (ग) में उल्लिखित आवश्यकताओं का पालन किया जाना चाहिए अर्थात् (क) टेस्टेटर को वसीयत पर हस्ताक्षर करना होगा या अपना निशान लगाना होगा, या इसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी उपस्थिति और निर्देश पर हस्ताक्षर करवाया जाना चाहिए; (ख) टेस्टेटर के हस्ताक्षर या निशान, या उसके निर्देश पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर को ऐसे स्थान पर दिखाई देना चाहिए जहां से यह प्रतीत हो कि उस निशान या हस्ताक्षर द्वारा दस्तावेज़ को वसीयत के रूप में प्रभावी



होना चाहिए; (ग) हमारे वर्तमान अपील में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जिसके साथ हम वर्तमान में चिंतित हैं, यह है कि वसीयत को दो या अधिक गवाहों द्वारा साक्ष्यांकित किया जाना चाहिए और इन गवाहों में से प्रत्येक ने टेस्टेटर को वसीयत पर हस्ताक्षर करते या निशान लगाते देखा हो, या किसी अन्य व्यक्ति को टेस्टेटर की उपस्थिति और निर्देश पर वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा हो, या टेस्टेटर से उसके हस्ताक्षर या निशान, या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत स्वीकृति प्राप्त की हो, और प्रत्येक गवाह ने टेस्टेटर की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किया हो।

9. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि वसीयत के उचित निष्पादन की आवश्यकताओं में से एक यह है कि इसे दो या अधिक गवाहों द्वारा साक्ष्यांकित किया जाना चाहिए, जो अनिवार्य है।

10. साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 इस बारे में बताती है कि कानून द्वारा साक्ष्यांकित आवश्यक दस्तावेज़ को कैसे साबित किया जा सकता है। इस धारा के अनुसार, एक दस्तावेज़ जिसे कानून द्वारा साक्ष्यांकित करना आवश्यक है, तब तक साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके निष्पादन को साबित करने के लिए कम से कम एक साक्ष्य गवाह को नहीं बुलाया गया हो, बशर्ते कि ऐसा साक्ष्य गवाह जीवित हो, अदालत की प्रक्रिया के अधीन हो और साक्ष्य देने में सक्षम हो। उत्तराधिकार



अधिनियम की धारा 63 को साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के साथ संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह प्रतीत होता है कि वसीयत प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि वसीयत का उचित और वैध निष्पादन हुआ है। यह केवल यह साबित करके नहीं किया जा सकता कि वसीयत पर हस्ताक्षर टेस्टेटर के थे, बल्कि यह भी साबित करना होगा कि साक्ष्यांकन उचित तरीके से किया गया था जैसा कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 (ग) में आवश्यक है। यह सच है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 यह नहीं कहती कि दोनों या सभी साक्ष्य गवाहों को जांचा जाना चाहिए। लेकिन कम से कम एक साक्ष्य गवाह को वसीयत के उचित निष्पादन को साबित करने के लिए बुलाया जाना चाहिए जैसा कि धारा 63 में परिकल्पित है। हालांकि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत वसीयत को कम से कम दो गवाहों द्वारा साक्ष्यांकित करना अनिवार्य है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 यह प्रावधान करती है कि एक दस्तावेज़, जिसे कानून द्वारा साक्ष्यांकित करना आवश्यक है, तब तक साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता जब तक कि कम से कम एक साक्ष्य गवाह को नहीं बुलाया गया हो, बशर्ते कि ऐसा साक्ष्य गवाह जीवित हो और सक्षम हो। एक तरह से, धारा 68 उन लोगों को रियायत देती है जो वसीयत को साबित करना और स्थापित करना चाहते हैं, यहां तक कि केवल एक साक्ष्य गवाह को जांचकर भी, हालांकि वसीयत को





उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत कम से कम दो गवाहों द्वारा साक्ष्यांकित करना अनिवार्य है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है और ध्यान देने योग्य है वह यह है कि जांचा गया एक साक्ष्य गवाह वसीयत के निष्पादन को साबित करने में सक्षम होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि एक साक्ष्य गवाह धारा 63 (ग) के तहत दो साक्ष्य गवाहों द्वारा साक्ष्यांकन को साबित कर सकता है, तो अन्य साक्ष्य गवाह की जांच को छोड़ा जा सकता है। जांचे गए एक साक्ष्य गवाह को अपने साक्ष्य में वसीयत के निष्पादन को साबित करना होगा, जिसमें उसके साक्ष्यांकन और अन्य साक्ष्य गवाह के साक्ष्यांकन को भी शामिल करना होगा ताकि यह साबित हो सके कि वसीयत का उचित निष्पादन हुआ था। यदि साक्ष्य गवाह, जिसे जांचा गया है, अपने साक्ष्य में अन्य साक्ष्य गवाह के साक्ष्यांकन को साबित करने में विफल रहता है, तो यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। जहां एक साक्ष्य गवाह को जांचा गया है और वह अन्य साक्ष्य गवाह के साक्ष्यांकन को साबित करने में विफल रहता है, तो वहां अन्य उपलब्ध साक्ष्य गवाह को बुलाया जाना चाहिए ताकि उसका साक्ष्य पूरक बन सके।

11. साक्ष्य अधिनियम की धारा 71, धारा 68 की अनिवार्य प्रावधानों को पूरा करने के लिए एक सुरक्षा उपाय के रूप में है, ताकि उस स्थिति से निपटा जा सके जहां साक्ष्य गवाहों को बुलाना संभव नहीं है,



हालांकि वे जीवित हैं। यह धारा प्रदान करती है कि यदि कोई साक्ष्य गवाह दस्तावेज़ के निष्पादन को इनकार करता है या याद नहीं करता है, तो इसके निष्पादन को अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। धारा 71 की सहायता केवल तभी ली जा सकती है जब साक्ष्य गवाह, जिन्हें बुलाया गया है, दस्तावेज़ के निष्पादन को इनकार करते हैं या याद नहीं करते हैं, तो इसे अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। धारा 71 का उपयोग उस मामले में नहीं किया जा सकता जहां एक साक्ष्य गवाह, जिसे अकेले बुलाया गया था, वसीयत के निष्पादन को साबित करने में विफल रहता है और अन्य साक्ष्य गवाह, हालांकि उपलब्ध हैं, को अज्ञात कारणों से अदालत में नहीं बुलाया गया है। यह धारा 71 के भाषा से स्पष्ट कि यदि कोई साक्ष्य गवाह दस्तावेज़ के निष्पादन को इनकार करता है या याद नहीं करता है, तो इसके निष्पादन को अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। हालांकि, उस मामले में जहां एक साक्ष्य गवाह की जांच वसीयत के उचित निष्पादन को साबित करने में विफल रहती है, यह नहीं कहा जा सकता कि वसीयत को धारा 68 के तहत साबित किया गया है। यह नहीं कहा जा सकता कि यदि एक साक्ष्य गवाह दस्तावेज़ के निष्पादन को इनकार करता है या याद नहीं करता है, तो वसीयत के निष्पादन को अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है, हालांकि अन्य साक्ष्य गवाह उपलब्ध हैं। इसके अलावा, यह कि





अन्य उपलब्ध साक्ष्य गवाहों को बुलाया जाना चाहिए जब एक साक्ष्य गवाह की जांच वसीयत के निष्पादन को साबित करने में विफल रहती है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 उदाहरण (छ) के तहत प्रतिकूल अनुमान लगाने के दावे को रोकने के लिए है। दिए गए परिस्थितियों में सर्वोत्तम संभव साक्ष्य को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मूल सिद्धांतों में से एक है। धारा 71 अनुमति देने वाली और सक्षम बनाने वाली धारा है जो कुछ परिस्थितियों में एक पक्ष को अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देती है। लेकिन धारा 68 केवल एक सक्षम बनाने वाली धारा नहीं है। यह उन आवश्यक आवश्यकताओं को निर्धारित करती है जिनका अदालत को पालन करना होगा इससे पहले कि यह माना जाए कि एक दस्तावेज़ साबित हो गया है। धारा 71 को इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता कि यह एक पक्ष को धारा 68 और उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत उसके दायित्व से मुक्त कर दे और उसे स्वतंत्रता दे कि वह अपनी इच्छा या पसंद के अनुसार एक आवश्यक गवाह को उपलब्ध कराए या न कराए और कानून के अनिवार्य प्रावधानों को नजरअंदाज करने पर प्रीमियम प्रदान करे। "

12. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63(ग) के तहत वसीयत के निष्पादन के संबंध में कानूनी आवश्यकता यह है कि वसीयत को दो या अधिक गवाहों द्वारा साक्ष्यांकित किया जाएगा, जिनमें



से प्रत्येक ने टेस्टेटर को वसीयत पर हस्ताक्षर करते या निशान लगाते देखा है या किसी अन्य व्यक्ति को टेस्टेटर की उपस्थिति और निर्देश पर वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा है, या टेस्टेटर से उसके हस्ताक्षर या निशान, या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत स्वीकृति प्राप्त की है; और प्रत्येक गवाह टेस्टेटर की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक से अधिक गवाह एक ही समय में उपस्थित हों, और साक्ष्यांकन के लिए किसी विशेष प्रारूप की आवश्यकता नहीं है।

13. उपरोक्त स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यह देखना होगा कि क्या साक्ष्य गवाहों ने वसीयत के निष्पादन को साबित किया है और क्या इसे इस आधार पर खारिज किया जाना चाहिए कि उनका साक्ष्य संदेह से मुक्त नहीं है।

14. सुदाम (DW2), जो किसी भी पक्ष से संबंधित नहीं हैं, ने बयान दिया है कि एक दिन मंगलू ने उन्हें दुमरपाली आने के लिए कहा और जब वे दुमरपाली पहुंचे, तो बुढ़निबाई, बतुराम और मंगलू मौजूद थे और हीरामती ने कहा कि वह कुछ कागजात तैयार करवाना चाहती हैं लेकिन किसके नाम पर, इस बारे में उन्होंने उस समय खुलासा नहीं किया। फिर, उन्होंने चौकीदार को बुलाया और हीरामती ने घोषणा की कि वह रायगढ़ जाकर कागजात तैयार करवाएंगी। उन्होंने हीरामती को उपसरपंच को साथ ले जाने का सुझाव दिया। अपने साक्ष्य के पैरा 5 में, यह गवाह बताता है कि अगले दिन वह बतुराम और सुरेश कुमार के साथ दुमरपाली गया। बुढ़निबाई पहले से मौजूद थीं और हीरामती ने उन्हें एक वाहन किराए पर लेने के लिए कहा और वे सभी वाहन में बैठकर रायगढ़ गए जहां मंगलू के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई। बाद में, मंगलू ने अपनी असमर्थता व्यक्त की और कहा कि वह भूमि नहीं चाहते क्योंकि वह किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते और उन्होंने सुझाव दिया कि वसीयत बसंत और बलुराम के पक्ष में निष्पादित की जाए। इस गवाह के आगे के साक्ष्य में यह है कि वह



सुरेश के साथ हीरामती के पास गया और फिर हीरामती ने कहा कि वह बतुराम के पक्ष में वसीयत निष्पादित करना चाहती हैं। फिर से सभी जीप में बैठे। वह सुरेश, मंगलू और अन्य के साथ रायगढ़ आया जहां बतुराम के नाम पर कागजात तैयार किए गए जिन पर उन्होंने और सुरेश ने हस्ताक्षर किए और हीरामती ने अपना अंगूठा लगाया और उसके बाद इसे जानकी प्रसाद द्वारा नोटरी किया गया। उन्होंने अपने हस्ताक्षर साबित किए हैं। उनसे विस्तृत जिरह की गई है। अपनी जिरह में, इस गवाह ने फिर से वसीयत के निष्पादन को स्वीकार किया और वसीयत के निष्पादन के विरुद्ध सभी सुझावों को नकार दिया है। उन्होंने यह सुझाव नकार दिया कि बतुराम के आग्रह पर मंगलू ने अपनी वसीयत रद्द कर दी। इस प्रकार, इस गवाह का साक्ष्य वसीयत के साक्ष्यांकन में इस गवाह की भूमिका के संबंध में कोई संदेह पैदा नहीं करता है।

15. अन्य गवाह सुरेश कुमार (DW3) ने भी वसीयत के निष्पादन को साबित किया है। उन्होंने बयान दिया है कि हीरामती ने बतुराम के पक्ष में वसीयत निष्पादित की और वसीयत हीरामती के निर्देशों और इच्छा के अनुसार तैयार की गई थी और उस समय हीरामती का स्वास्थ्य ठीक था। इस गवाह से भी विस्तृत जिरह की गई। पैरा 14 में, उन्होंने कहा है कि हीरामती ने अपनी इच्छा से वसीयत निष्पादित करवाई। यद्यपि इस गवाह से विस्तृत जिरह की गई, वसीयत के निष्पादन के साक्ष्य गवाह के रूप में इस गवाह की विश्वसनीयता को चुनौती देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस संबंध में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 (ग) और साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 की कानूनी आवश्यकताएं पूरी होती हैं।

16. इस प्रकार, जब वसीयत का निष्पादन कानून के प्रावधानों के अनुसार न केवल एक बल्कि दोनों साक्ष्य गवाहों द्वारा साबित किया गया है, तो निचली अदालतों को अन्य गवाहों के साक्ष्य का मूल्यांकन करना चाहिए था ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन सी असाधारण परिस्थितियां थीं जो वसीयत को पूरी तरह से खारिज करने वाली थीं, विशेष रूप से जब इसका निष्पादन साक्ष्य गवाहों द्वारा साबित किया गया था। वसीयत पर संदेह करने के लिए, निचली अदालतों ने यह निष्कर्ष निकाला कि



हीरामती का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। सबसे पहले, केवल इस आधार पर कि कोई व्यक्ति वृद्ध है और स्वस्थ नहीं है, यह नहीं माना जा सकता कि वह वसीयत निष्पादित करने की स्थिति में नहीं था। एक बार वसीयत का निष्पादन साक्ष्य गवाहों द्वारा साबित हो जाने के बाद, वसीयत को चुनौती देने वाले पक्ष पर बोझ बहुत अधिक होता है। इसलिए, यह साबित करने के लिए स्पष्ट, ठोस और निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है कि वसीयत कर्ता, वसीयत के निष्पादन के समय, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम था और यह नहीं कहा जा सकता कि टेस्टेटर ने स्वेच्छा से लाभार्थी के पक्ष में वसीयत निष्पादित की थी। वादी द्वारा प्रस्तुत दलीलें और साक्ष्य यह है कि हीरामती वृद्ध थीं और बिस्तर पर पड़ी रहती थीं और उनके दैनिक कार्य भी बिस्तर पर ही किए जाते थे। सुकेत (PW1) ने कहा है कि मृत्यु से लगभग 11/2 महीने पहले, हीरामती बिस्तर पर पड़ी रहती थीं और उनके दैनिक कार्य बिस्तर पर ही किए जाते थे। उन्होंने कहा कि उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। हालांकि, यह साक्ष्य बहुत अस्पष्ट है। जिरह के पैरा 8 में, हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने डॉक्टर को बुलाया था, वह डॉक्टर का नाम नहीं जानतीं और न ही उन्होंने हीरामती के उपचार से संबंधित कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है। इस प्रकार, उनका साक्ष्य केवल यह साबित करता कि हीरामती बिस्तर पर पड़ी रहती थीं, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं हैं, सिवाय एक सामान्य बयान के, और कोई दस्तावेज़ या चिकित्सक का प्रमाणपत्र नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि टेस्टेटर ने मानसिक संतुलन खो दिया था।

17. अन्य गवाह पीठाम्बर (PW2) ने कहा है कि उनकी मृत्यु से दो महीने पहले, हीरामती चलने में असमर्थ थीं और ज्यादातर बिस्तर पर ही रहती थीं। उन्होंने उनकी मानसिक स्थिति के बारे में

कुछ नहीं कहा। तीसरे गवाह, बिंदुबाई (PW3) ने भी कहा है कि हीरामती का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और वह अकेले अपने घर में रहती थीं। इसके अलावा, उनके साक्ष्य में और कुछ नहीं कहा गया है। गोविंदराम गोड़ा (PW4) ने अपने साक्ष्य के पैरा 5 में बयान दिया है कि उनकी मृत्यु से लगभग 8 दिन पहले, हीरामती ने होश खो



दिया था। यदि यह साक्ष्य स्वीकार किया जाता है, तो यह स्वीकार किया जाता है कि वसीयत 09/03/1999 को निष्पादित की गई थी और हीरामती की मृत्यु 26/03/1999 को हुई थी, उपरोक्त साक्ष्य यह साबित नहीं करता कि वसीयत निष्पादित करने की तिथि को हीरामती ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और शारीरिक और मानसिक रूप से वसीयत निष्पादित करने के लिए अयोग्य थीं।

18. प्रतिवादी के वकील ने इस न्यायालय का ध्यान प्रतिवादी – बतुराम (DW1) के साक्ष्य की ओर आकर्षित किया कि उन्होंने यह भी कहा है कि हीरामती का स्वास्थ्य ठीक नहीं था । यदि स्वास्थ्य स्थिति के संबंध में उनके पूरे साक्ष्य को ध्यान में रखा जाए, तो वादी या प्रतिवादी के किसी भी गवाह ने यह साबित नहीं किया है कि हीरामती इतनी शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हो गई थीं कि वह वसीयत निष्पादित नहीं कर सकती थीं। कोई भी साक्ष्य नहीं है कि हीरामती ने मानसिक संतुलन खो दिया था और उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि उनसे वसीयत निष्पादित करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी । केवल इस आधार पर कि हीरामती एक वृद्ध महिला थीं और बिस्तर पर पड़ी रहती थीं, इस आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह वसीयत निष्पादित करने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थीं। निचली अदालतों के इस पहलू पर निष्कर्ष अधिकतर अनुमान पर आधारित हैं न कि निर्णायक साक्ष्य पर। निचली अदालतों का दृष्टिकोण मूल रूप से त्रुटिपूर्ण है क्योंकि एक बार निष्पादन विश्वसनीय साक्ष्य से साबित हो जाने के बाद, केवल टेस्टेटर के वृद्ध और बिस्तर पर पड़े होने के आधार पर, उनके मानसिक रूप से अयोग्य होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। निचली अदालतों ने, यदि मैं कह सकता हूं, कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य के बिना निष्कर्ष पर कूद गई और इसलिए, ऐसा निर्णय गंभीर विपरीतता से ग्रस्त है।

19. वसीयत को संदिग्ध मानने के लिए जिन अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया है, वह यह है कि बतुराम, जिसके पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई थी, ने सक्रिय भूमिका निभाई। यह सच है कि जिस व्यक्ति के पक्ष में वसीयत निष्पादित की



गई है, उसने सक्रिय भूमिका निभाई है। वसीयत के प्रमाण के संबंध में साक्ष्य का अत्यंत सावधानी और सतर्कता के साथ मूल्यांकन किया जाना चाहिए और साथ ही यह नहीं कहा जा सकता कि सभी मामलों में वसीयत को खारिज कर दिया जाना चाहिए, भले ही इसे विश्वसनीय साक्ष्य गवाहों द्वारा साबित किया गया हो।

20. निचली अपीलीय अदालत ने भी वसीयत पर इस आधार पर संदेह व्यक्त किया है कि पहले पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई थी और फिर इसे रद्द कर दिया गया और बतुराम के पक्ष में नई वसीयत निष्पादित की गई, जिसे उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। सबसे पहले, किन परिस्थितियों में वसीयत निष्पादित की गई और किन परिस्थितियों में मंगलू के पक्ष में निष्पादित वसीयत को रद्द किया गया, इस बारे में साक्ष्य गवाहों सुदाम (DW2) और सुरेश कुमार (DW3) द्वारा बयान दिया गया है। इस संबंध में साक्ष्य यह है कि पहले मंगलू के पक्ष में एक वसीयत निष्पादित की गई थी, लेकिन विवाद के आशंका के कारण, मंगलू ने अपनी असमर्थता व्यक्त की, और फिर टेस्टेटर से संपर्क किया गया और टेस्टेटर ने मंगलू के पक्ष में पहले निष्पादित वसीयत को रद्द कर बतुराम के पक्ष में नई वसीयत निष्पादित करने की इच्छा व्यक्त की । वसीयत (Ex.D-4) के अवलोकन से, स्पष्ट उल्लेख है कि मंगलू के पक्ष में निष्पादित वसीयत को रद्द कर दिया गया था। निचली अपीलीय अदालत द्वारा किया गया मूल्यांकन सुदाम (DW2), सुरेश कुमार (DW3), और जानकी प्रसाद (DW4) द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट साक्ष्य के उचित विचार / मूल्यांकन के बिना है, लेकिन अन्य परिस्थिति यह है कि हीरामती की मृत्यु के तुरंत बाद बतुराम के नाम पर वसीयत का खुलासा नहीं किया गया। इस न्यायालय की राय में, यह स्वयं में संदिग्ध परिस्थिति नहीं है। वादी के दो गवाहों पीठाम्बर (PW3) और गोविंदराम गोड़ा (PW4) का साक्ष्य यह है कि हीरामती स्वयं वसीयत निष्पादित करने रायगढ़ गई थीं। यह वही है जो सभी गवाहों, जिनमें सुदाम (DW2) और सुरेश कुमार (DW3) शामिल हैं, ने कहा है। यह वादी के मामले के विपरीत है कि हीरामती शारीरिक और मानसिक रूप से वसीयत निष्पादित करने के लिए अयोग्य थीं।



21. प्रतिवादी का साक्ष्य यह भी है कि बतुराम हीरामती का भतीजा था और वह उनकी भूमि पर कृषि गतिविधियाँ कर रहा था और अपनी मौसी - हीरामती की देखभाल भी कर रहा था। वास्तव में, साक्ष्य से यह पता चलता है कि मंगलू और बतुराम दोनों देखभाल कर रहे थे।

22. उपरोक्त के आधार पर, निचली अदालतों का यह निष्कर्ष कि वसीयत संदिग्ध है, गंभीर विपरीतता और स्पष्ट अवैधता से ग्रस्त है, क्योंकि इसमें वसीयत के प्रमाण के मामले में साक्ष्य के मूल्यांकन के सही सिद्धांतों को लागू करने में विफल रहा है। कानूनी प्रश्न को तदानुसार निर्णीत किया गया है।

23. परिणामस्वरूप, निचली अदालतों द्वारा पारित आरोपित निर्णय और डिक्री कानून में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं और इसे अपास्त किया जाता है। वादी का मुकदमा खारिज किया जाता है। पक्षकार अपने-अपने खर्च वहन करेंगे। अपीलीय डिक्री तदानुसार तैयार की जाए।

सही / -
(मनींद्र मोहन श्रीवास्तव)
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।